

# रजिस्टर डाक ए .डी .द्वारा

क फाइल संख्या (File No.) : V2(STC)91 /North/Appeals/ 2017-18

ख अपील आदेश संख्या (Order-In-Appeal No.): <u>AHM-EXCUS-002-APP- 395-17-18</u> दिनांक (Date): <u>26-Mar-2018</u> जारी करने की तारीख (Date of issue): <u>/६/५/2018</u> श्री उमा शंकर, आयुक्त (अपील-II) द्वारा पारित Passed by **Shri Uma Shanker**, Commissioner (Appeals)

ग \_\_\_\_\_ आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, (मंडल-VI), अहमदाबाद उत्तर, आयुक्तालय द्वारा जारी मूल आदेश सं \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ से सृजित
Arising out of Order-In-Original No <u>GST-06/Refund/15/AC/KMM/Imark/2017-2018</u>

Dated: 15/11/2017
issued by: Assistant Commissioner Central Excise (Div-VI), Ahmedabad North

घ अपीलकर्ता/प्रतिवादी का नाम एवम पता (Name & Address of the Appellant/Respondent)

#### M/s Imark Info360 Pvt. Ltd

कोई व्यक्ति इस अपील आदेश से असंतोष अनुभव करता है तो वह इस आदेश के प्रति यथास्थिति नीचे बताए गए सक्षम अधिकारी को अपील या पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत कर सकता है |

Any person an aggrieved by this Order-in-Appeal may file an appeal or revision application, as the one may be against such order, to the appropriate authority in the following way:

भारत सरकार का पुनरीक्षण आवेदन :

### Revision application to Government of India:

(1) (क) (i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994 की धरा अतत नीचे बताए गए मामलों के बारे में पूर्वोक्त धारा को उप-धारा के प्रथम परंतुक के अंतर्गत पुनरीक्षण आवेदन अधीन सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, चौथी मंजिल, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को की जानी चाहिए |

A revision application lies to the Under Secretary, to the Government of India, Revision Application Unit, Ministry of Finance, Department of Revenue, 4th Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001, under Section 35EE of the CEA 1944 in respect of the following case, governed by first proviso to sub-section (1) of Section-35 ibid:

(ii) यदि माल की हानि के मामले में जब हानि कारखाने से किसी भंडारगार या अन्य कारखाने में या किसी भंडारगार से दूसरे भंडारगार में माल ले जाते हुए मार्ग में, या किसी भंडारगार या भंडार में चाहे वह किसी कारखाने में या किसी भंडारगार में हो माल की प्रकिया के दौरान हुई हो |

In case of any loss of goods where the loss occur in transit from a factory to a warehouse or to another factory or from one warehouse to another during the course of processing of the goods in a warehouse or in storage whether in a factory or in a warehouse

(ख) भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित माल पर या माल के विनिर्माण में उपयोग शुल्क कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क के रिबेट के मामले में जो भारत के बाहर किसी राष्ट्र या प्रदेश में निर्यातित है।

Cont...2

2396 to 2400

(c) In case of goods exported outside India export to Nepal or Bhutan, without payment of duty.

अंतिम उत्पादन की उत्पादन शुल्क के भुगतान के लिए जो डयूटी केंडिट मान्य की गई है और ऐसे आदेश जो इस धारा एवं नियम के मुताबिक आयुक्त, अपील के द्वारा पारित वो समय पर या बाद में वित्त अधिनियम (नं.2) 1998 धारा 109 द्वारा नियुक्त किए गए हो।

- (d) Credit of any duty allowed to be utilized towards payment of excise duty on final products under the provisions of this Act or the Rules made there under and such order is passed by the Commissioner (Appeals) on or after, the date appointed under Sec.109 of the Finance (No.2) Act, 1998.
- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 के नियम 9 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रपन्न संख्या इए–8 में दो प्रतियों में, प्रेषित आदेश के प्रति आदेश प्रेषित दिनाँक से तीन मास के भीतर मूल–आदेश एवं अपील आदेश की दो–दो प्रतियों के साथ उचित आवेदन किया जाना चाहिए। उसके साथ खाता इ. का मुख्यशीर्ष के अंतर्गत धारा 35–इ में निर्धारित फी के भुगतान के सबूत के साथ टीआर–6 चालान की प्रति भी होनी चाहिए।

The above application shall be made in duplicate in Form No. EA-8 as specified under Rule, 9 of Central Excise (Appeals) Rules, 2001 within 3 months from the date on which the order sought to be appealed against is communicated and shall be accompanied by two copies each of the OIO and Order-In-Appeal. It should also be accompanied by a copy of TR-6 Challan evidencing payment of prescribed fee as prescribed under Section 35-EE of CEA, 1944, under Major Head of Account.

(2) रिविजन आवेदन के साथ जहाँ संलग्न रकम एक लाख रूपये या उससे कम हो तो रूपये 200/— फीस भुगतान की जाए और जहाँ संलग्न रकम एक लाख से ज्यादा हो तो 1000/— की फीस भुगतान की जाए।

The revision application shall be accompanied by a fee of Rs.200/- where the amount involved is Rupees One Lac or less and Rs.1,000/- where the amount involved is more than Rupees One Lac.

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रति अपील:--Appeal to Custom, Excise, & Service Tax Appellate Tribunal.

- (1) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35-बी/35-इ के अंतर्गत:-Under Section 35B/ 35E of CEA, 1944 an appeal lies to :-
- (क) वर्गीकरण मूल्यांकन से संबंधित सभी मामले सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण की विशेष पीठिका वेस्ट ब्लॉक नं. ३. आर. के. पुरम, नई दिल्ली को एवं
- (a) the special bench of Custom, Excise & Service Tax Appellate Tribunal of West Block No.2, R.K. Puram, New Delhi-1 in all matters relating to classification valuation and.
- (ख) उक्तलिखित परिच्छेद 2 (1) क में बताए अनुसार के अलावा की अपील, अपीलो के मामले में सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट) की पश्चिम क्षेत्रीय पीठिका, अहमदाबाद में ओ—20, न्यू मैन्टल हास्पिटल कम्पाउण्ड, मेघाणी नगर, अहमदाबाद—380016.
- (b) To the west regional bench of Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) at O-20, New Metal Hospital Compound, Meghani Nagar, Ahmedabad : 380 016. in case of appeals other than as mentioned in para-2(i) (a) above.
- (2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (अपील) नियमावली, 2001 की धारा 6 के अंतर्गत प्रपन्न इ.ए—3 में निर्धारित किए अनुसार अपीलीय न्यायाधिकरणें की गई अपील के विरुद्ध अपील किए गए आदेश की चार प्रतियाँ सहित जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या उससे कम है वहां रूपए 1000/— फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 5 लाख या 50 लाख तक हो तो रूपए 5000/— फीस भेजनी होगी। जहाँ उत्पाद शुल्क की मांग, ब्याज की मांग ओर लगाया गया जुर्माना रूपए 50 लाख या उससे ज्यादा है वहां रूपए 10000/— फीस भेजनी होगी। की फीस सहायक रिजस्टार के नाम से

रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंध की जाये। यह ड्राफ्ट उस स्थान के किसी नामित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखा का हो जहाँ उक्त न्यायाधिकरण की पीठ स्थित है।

The appeal to the Appellate Tribunal shall be filed in quadruplicate in form EA-3 as prescribed under Rule 6 of Central Excise(Appeal) Rules, 2001 and shall be accompanied against (one which at least should be accompanied by a fee of Rs.1,000/-, Rs.5,000/- and Rs.10,000/- where amount of duty / penalty / demand / refund is upto 5 Lac, 5 Lac to 50 Lac and above 50 Lac respectively in the form of crossed bank draft in favour of Asstt. Registar of a branch of any nominate public sector bank of the place where the bench of any nominate public sector bank of the place where the bench of the Tribunal is situated.

(3) यदि इस आदेश में कई मूल आदेशों का समावेश होता है तो प्रत्येक मूल ओदश के लिए फीस का भुगतान उपर्युक्त ढंग से किया जाना चाहिए इस तथ्य के होते हुए भी कि लिखा पढी कार्य से बचने के लिए यथास्थिति अपीलीय न्यायाधिकरण को एक अपील या केन्द्रीय सरकार को एक आवेदन किया जाता हैं।

In case of the order covers a number of order-in-Original, fee for each O.I.O. should be paid in the aforesaid manner not withstanding the fact that the one appeal to the Appellant Tribunal or the one application to the Central Govt. As the case may be, is filled to avoid scriptoria work if excising Rs. 1 lacs fee of Rs.100/- for each.

(4) न्यायालय शुल्क अधिनियम 1970 यथा संशोधित की अनुसूचि—1 के अंतर्गत निर्धारित किए अनुसार उक्त आवेदन या मूल आदेश यथास्थिति निर्णयन प्राधिकारी के आदेश में से प्रत्येक की एक प्रति पर रू.6.50 पैसे का न्यायालय शुल्क टिकट लगा होना चाहिए।

One copy of application or O.I.O. as the case may be, and the order of the adjournment authority shall a court fee stamp of Rs.6.50 paise as prescribed under scheduled-I item of the court fee Act, 1975 as amended.

(5) इन ओर संबंधित मामलों को नियंत्रण करने वाले नियमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है जो सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (कार्याविधि) नियम, 1982 में निहित है।

Attention in invited to the rules covering these and other related matter contended in the Customs, Excise & Service Tax Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 1982.

(6) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सिस्टेट), के प्रति अपीलो के मामले में कर्तव्य मांग (Demand) एवं दंड (Penalty) का 10% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। हालांकि, अधिकतम पूर्व जमा 10 करोड़ रुपए है। (Section 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के अंतर्गत, शामिल होगा "कर्तव्य की मांग"(Duty Demanded) -

- (i) (Section) खंड 11D के तहत निर्धारित राशि;
- (ii) लिया गलत सेनवैट क्रेडिट की राशि;
- (iii) सेनवैट क्रेडिट नियमों के नियम 6 के तहत देय राशि.

⇒ यह पूर्व जमा 'लंबित अपील' में पहले पूर्व जमा की तुलना में, अपील' दाखिल करने के लिए पूर्व शर्त बना दिया गया है.

For an appeal to be filed before the CESTAT, 10% of the Duty & Penalty confirmed by the Appellate Commissioner would have to be pre-deposited. It may be noted that the pre-deposit is a mandatory condition for filing appeal before CESTAT. (Section 35 C (2A) and 35 F of the Central Excise Act, 1944, Section 83 & Section 86 of the Finance Act, 1994)

Under Central Excise and Service Tax, "Duty demanded" shall include:

- (i) amount determined under Section 11 D;
- (ii) amount of erroneous Cenvat Credit taken;
- (iii) amount payable under Rule 6 of the Cenvat Credit Rules.

इस सन्दर्भ में ,इस आदेश के प्रति अपील प्राधिकरण के समक्ष जहाँ शुल्क अथवा शुल्क या दण्ड विवादित हो तो माँग किए गए शुल्क के 10% भुगतान पर और जहाँ केवल दण्ड विवादित हो तब दण्ड के 10% भुगतान पर की जा सकती है।

In view of above, an appeal against this order shall lie before the Tribunal on payment of 10% of the duty demanded where duty or duty and penalty are in dispute, or penalty, where penalty alone is in dispute."

### **ORDER IN APPEAL**

3

M/s Imark Info360 Pvt. Ltd, 401-405, Gala Mart, Off South Bopal Road, Nr. Sun City, Bopal, Ahmedabad, Gujarat, Pin 380 058 (hereinafter referred to as 'appellants') have filed the present appeals against the Order-in-Original No. GST-06/Refund/15/AC/KMM/IMARK/2017-18 dated 15.11. 2017 (hereinafter referred to as 'impugned orders') passed by the Asst. Commissioner, Service Tax, Div-I (now CGST Div- VI, Ahmedabad North), having office at B. D. Patel House, Nr. Sardar Patel Statue, Naranpura, Ahmedabad-13 (hereinafter referred to as 'adjudicating authority').

2. The facts of the case, in brief are that appellant (STR AACC I9806R SD001) have filed refund claim for Rs. 2,06,650/- on 12.06.2017 for the period-half year ending on 31.03.2016, in terms of notification No. 27/2012-CE (NT) dated 18.06.2012.

#### NNNNNNNNNNN

- 3. Whole claim was rejected on following grounds
  - i. Instead of filing claim on quarterly basis as required in condition at para No. 2(a), 2(b) and 2(c) of Notification No. 27/2012-CE (NT) appellant filed claim on half yearly basis (para 5.1(b) para 7.6 of OIO).
- ii. Refund of SB Cess Rs. 6,890/- is not admissible, therefore column No. 5 of claim should be 1,99,760/- instead of Rs. 2,06,650/- para 5.1(c)
- iii. Non submission of various documents and non matching of various documents figures with claim submitted.
- iv. Export turnover Value calculated in terms of Rule 5(1)(D) of CER, 2002, figures did not match with inward remittance figures and ST-3 and application form-A [ 5.1 (e) and para 7.5(a) 7.5(B)].
- 4. Being aggrieved with the impugned order, the appellants preferred an appeal on 13.02.2018 before the Commissioner Appeals, CGST, GST Bhavan, Ambawadi, Ahmadabad wherein it is contended that
  - i. The appellant was issued deficiency memo, however the order rejecting entire refund was issued without issuance of SCN and awarding the opportunity of being heard. Principal of natural justice is not complied in present case.
- ii. Appellant can file claim on half yearly basis.
- iii. Regarding arithmetical difference in turnover and calculation pointed out by adjudicating authority it is submitted that whatever is alleged is explainable and can be explained if proper opportunity is granted.
- iv. Refund is allowed under Notification No. 39/2012-ST alternatively for Swatch Bharat Cess (SB cess).

<sup>\*</sup> 5. Personal hearing in the case was granted on 14.03.2018. Shree Pravin Dhandhariya, CA, appeared before me and reiterated the grounds of appeal. He stated that for various reasons the hearing was not granted/attended and he requested for remand.

### DISUSSION AND FINDINGS

- 6. I have carefully gone through the facts of the case on records, grounds of appeal in the Appeal Memorandum and oral/written submissions made by the appellants, evidences produced at the time of personal hearing.
- 7. Claim was rejected on grounds stated above in para 3(i) of this order. Claim is required to be filed on quarterly basis in terms of notification but if it is filed on half yearly basis then it may be bifurcated and processed on quarterly basis and benefits may be granted if otherwise admissible. I find that appellant had not replied deficiency memo and personal hearing was not granted in the matter before rejecting the refund. Appellant had pleaded that had they been given opportunity of personal hearing they would have explained the adjudicating authority regarding all grounds taken in OIO to reject the claim. Appellant has requested to remand the case back to original adjudicating authority so that he can prove his stand.
- 8. I find that deficiency memo was issued but no proper SCN was issued before passing of OIO. Case was decided ex-parte and claim was rejected. In view of appellants request and submissions, also in view of proper compliance on natural justice and also in view of facts that substantial benefits should not be denied to exported for mere procedural/ technical lapse, without going in to merit of the case I am inclined the remand the case back to original adjudicating authority to decide the case afresh after issuing SCN elaborating all grounds and after affording personal hearing in the case.
- 9. In view of facts and discussion herein above, the Adjudicating Authority is directed to decide the case afresh, for which case is remanded back to the Adjudicating Authority, after due compliance of the principles of natural justice and after proper appreciation of the evidences that may be put forth by the appellant before him. The appellant is also directed to bifurcate claim on quarterly basis and directed to put all the evidences before the Adjudicating Authority in support of their contention as well as any other 4



details/documents etc. that may be asked for by the Adjudicating Authority when the matter is heard in remand proceedings before the Adjudicating Authority. These findings of mine are supported by the decision/order dated 03.04.2014 of the Hon'ble High Court, Gujarat in the Tax appeal No.276//2014 in the case of Commissioner, Service Tax, Ahmedabad V/s Associated Hotels Ltd. and also by the decision of the Hon'ble CESTAT, WZB Mumbai in case of Commissioner of Central Excise, Pune-I Vs. Sai Advantium Ltd and reported in 2012 (27) STR 46 (Tri. – Mumbai).

- 10. In view of above, appeal filed by the appellants is allowed by way of remand.
- 11. अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई अपीलों का निपटारा उपरोक्त तरीके से किया जाता है।
- 11. The appeals filed by the appellant stand disposed off in above terms.

(उमा शंकर)

केन्द्रीय कर आयुक्त (अपील्स)

**ATTESTED** 

(R.R. PATEL)

SUPERINTENDENT (APPEAL),

CENTRAL TAX, AHMEDABAD

To,

M/s Imark Info360 Pvt. Ltd, 401-405, Gala Mart, ff South Bopal Road, Nr. Sun City, Bopal, Ahmedabad, Gujarat, Pin 380 058

## Copy to:

- 1. The Chief Commissioner, Central Tax, Ahmedabad
- 2. The Commissioner Central Tax, CGST, Ahmedabad North, , Customs House, Navrangpura, Ahmedabad

- 3. The Asst. Commissioner, CGST Div- VI, Ahmedabad North Commissionerate having office at at B. D. Patel House, Nr. Sardar Patel Statue, Naranpura, Ahmedabad-13
- 4. The Asst. Commissioner (System), Ahmedabad North, , Customs House, Navrangpura, Ahmedabad
- 5. Guard File
- 6. P.A. File

•			ø)
•	_ :	•	